

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-18 मई, 2011

विषय:-जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार नगर की पुनर्गठन पेयजल योजना के पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्र संख्या 2774/नग0अनु0/जेएनएनयूआरएम दिनांक 16-12-2010 के द्वारा प्रेषित जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर की पुनर्गठन पेयजल योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 7687.00 लाख को टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ₹ 7081.55 लाख संस्तुत किये गये हैं।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत उपरोक्त परियोजना लागत ₹ 7081.55 लाख में से उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा संस्तुत परियोजना लागत ₹ 4784.43 लाख तथा राज्य सैक्टर से पूर्व में स्वीकृत अतिरिक्त लागत ₹ 853.00 लाख को घटाते हुए राज्य सैक्टर से ₹ 1444.12 लाख की अतिरिक्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 500.00 लाख (₹ पांच करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा उक्त धनराशि को अपने पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी।

2. पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति भारत सरकार से कराकर उसके सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाय एवं तदक्रम में यदि भारत सरकार पुनरीक्षित डी०पी०आर० पर सहमति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करती है, तो अतिरिक्त लागत एवं उसके सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का समायोजन, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से कर लिया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
5. उक्त धनराशि को पेयजल निगम को अवमुक्त किये जाने से पूर्व पेयजल निगम के साथ MoA हस्ताक्षरित करते हुए शासन की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
11. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
13. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
14. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
15. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 66/XXVII(2)/2011, दिनांक- 10 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।


649
सं० (1)/IV(2)-शा०वि०-11, तददिनांक। 18-5-11

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी.सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी।
6. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।

10. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
13. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,


(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।